RAJYA SABHA

Wednesday, the 18th March, 1992/28 Phalguna, 1913 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

OBITUARY REFERENCE

MR CHAIRMAN: Hon. Members must have heard about the sad demise of Shri Shriyans Prasad Jain, a former Member of the Rajya Sabha, who passed away after prolonged illness on the 17th March, 1992 at the age of 84 years. He was a Member of this House representing the erstwhile State of Bombay from 1952 to 1958.

Born at Najibabad in Bijnor district of Uttar Pradesh in November 1908, Shri Jain got his education at Government School, Najibabad. An industrialist by vocation, he was closely associated with the country's struggle for freedom. He actively participated in the 'Quit India' movement and suffered imprisonment.

A freedom fighter, connoisseur of Urdu poetry and industrialist, Shri Jain lived a full life. A man of deep culture, Shri Jain took keen interest in the promotion of girls' education and other cultural activities. He was also associated with several charitable, educational and medical institutions.

In the recognition of his services to the country, he was honoured with the titles of 'Shriyans Abhinav' and 'Samaj Shiromoni'. He was awarded a 'Tamra Patra' by the All India Digambar Jain Parishad for his services to the Jain community and the public at large. The Government of Maharashtra honoured him with a Sanman Patra—a certificate of honour as freedom fighter. For his outstanding contributions he was also awarded the 'Padma Bhushan'.

In his death, the country has lost a patriot, an able industrialist, a philanthropist and a stunch advocate of Sarva Dharma Sambhava.

We deeply mourn the passing away of Shri Shriyans Prasad Jain.

I request Members to rise in their places and observe a silence as a mark of respect to the memory of the departed.

(Hon. Members then stood in silence of one minute).

MR. CHAIRMAN: Secretary-General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Goodwill Mission to Kashmir Valley

*301. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that fundamentalism and violence are on the increase in the Kashmir Valley;

(b) if so, whether Government propose to send a goodwill delegation of religious leaders having nationalist feelings or an all party goodwill delegation to the Valley to pacify and mould public opinion there; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The law and order situation in the State, particularly in the Kashmir Valley, continues to be difficult due to activities of the terrorists, aided and abetted by Pakistan who have been exploiting the religious feelings of the people. Fear of the gun is also still pervasive in the Valley. In this situation, there is no proposal to send

a delegation of religious leaders or an all party goodwill delegation to the Valley. Efforts are, however, being continued to strengthen inter-action with the common people. and to have regular consultations with political leaders and prominent personalities to recommence the political process.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : सभापति महोदय, सरकार ने सदन में यह घोषणा की है कि पंजाब के चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर में भी जल्दी ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी । लेकिन आज मेरे प्रश्न के उत्तर में जो तथ्य गृह मंत्री महोदय ने रखे हैं उनसे यह लगता है कि उनके उस आश्वासन में और इस उत्तर में बहुत अन्तर है । यह जो स्थिति की गम्भीरता यहां बताई गई है उससे यह लगता है कि अभी नजदीक भविष्य में कोई चुनाव करने की स्थिति में नहीं है । मैं एक बात और कहना चाहता हूं ।

श्री सभापति : आप प्रश्न कर लीजिये और जल्दी-जल्दी कीजिये ।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैं प्रश्न के बारे में ही कह रहा हूं । सरकार अचानक यह घोषणा करती है कि स्थिति खराब है और अचानक यह कहेगी कि अब स्थिति ठीक हो गई है । मैं समझता हूं कि एकता यात्रा के बारे में यह कहा गया कि उससे वहां आतंकवादी इकट्ठा हो गये । लेकिन पंजाब के चुनावों में आतंकवादी भी और राजनैतिक दल भी जिस तरह से एलियनेट हुए हैं वह स्थिति वहां दोहराई न जाये, इसके लिए पहले मैं गृह मंत्री महोदय से यह पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस समय क्या जम्मू-कश्मीर और विशेष रूप से काश्मीर घाटी में, स्थिति को ठीक करने के लिए आतंकवादियों के विरुद्ध तलाशी अभियान चलाने का विचार रखते हैं और दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि वहां पर जो प्रशासन चल रहा है और वह प्रशासन बिलकुल विफल हो रहा है और मुझे यह जानकारी है कि लोगों को छोड़ दिया जाता है... (व्यवधान) ।

श्री सभापति : आप प्रश्न कर लीजिये ।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि वहां पर जो लोगों को किडनेप करने की और छोड़ने की घटनायें हो रही हैं, उसमें क्या यह प्रश्न भी जुड़ा हुआ है कि इनके साथ कुछ टेरोरिस्ट्स को भी छोड़ा जा रहा है ? यह मैं अपना पहले पूरक प्रश्न रख रहा हूं ।

SHRI S. B. CHAVAN: Sir. we are trying to assess the situation in Jammu and Kashmir. But our intention is very clear, that we would like to have a duly elected Government in Jammu and Kashmir as early as possible. which depends on the kind of assessment that we ultimately will have. About the terrorist activity and the action taken by the Government against them, we are consistently following and flushing them out from certain areas in order to create normalcy with a view to staring a political dialogue. It will not be out of place Sir. if I have to bring to the notice of the honourable House that we had about four meetings. The first meeting was held on 13th November 1991 where political parties and prominent personalities of the State were specially invited. In the Consultative Committee, the Jammu and Kashmir issue was specially discussed on 13th December 1991. At the National Integration Council, on 31st December 1991 this issue was discussed and an All-Party Conference deliberated on the situation in Jammu and Kashmir on 10th February 1992. Thereafter, this *Ekta Yatra* had gone there which, in fact, created some more problems for the Government, and that's why we will have to again reasses the situation and find out as to how best we will be able to hold elections in that area.

SHRI VIREN J. SHAH: Extraordinary statement, Sir, extra-ordinary about the *Ekta Yatra* I don't think it befits the Home Minister to say that.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न छोटा-सा है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या जम्मू-कश्मीर में अब भी यह स्थिति है कि वहां पर कुछ स्थानीय संस्थाओं के चुनाव नहीं हो सकते हैं ? मेरे हिसाब से जम्मू रीजन और लद्दाख रीजन में आतंकवाद की कोई समस्या नहीं है । एक बड़े हद तक वहां पर स्थानीय चुनावों से कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है । इसलिए क्या सरकार ऐसा सोचती है कि वहां पर स्थानीय संस्थाओं के चुनाव जो काफी वर्षों से नहीं हुए हैं, वे चुनाव शीघ्र कराये जायें ताकि तीनों रीजन्स के प्रति कम से कम न्याय की भावना पैदा हो सके ?

SHRI S. B. CHAVAN: Sir, on the point whether to hold the Assembly elections first or the local bodies' elections first, I feel that it would be advisable to hold the Assembly elections first, and thereafter we can hold the local bodies' elections.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : पंजाब में तो पहले लोकल बाडीज के चुनाव हुए, लेकिन यहां असेम्बली के होंगे ?

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगी...

श्री सभापति : आप प्रश्न कर लीजिये ...(**व्यवधान**)... आप चाहती हैं आपको बधाई भी दे सकता हूं ।

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : काश्मीर में ...(**व्यवधान**)...

SHRI KAPIL VERMA: We should congratulate her.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : कांग्रेस में आते ही शादी हो गयी ।... (**व्यवधान**)...

श्री सभापति : सरदार जी इनविटेशन दे रहे हैं शर्मा जी को कि जो भी इधर आता है वह भाग्यशाली हो जाता है । उनकी भी शादी हो जायेगी ।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मुझे कम से कम निमंत्रण तो भिजवाइये ।...(**व्यवधान**)

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : सभापति महोदय, पंजाब...(**व्यवधान**)...

सभापति महोदय, पंजाब में जो चुनाव हुए है उसके परिणाम को देखते हुए यह लगता है कि पूरे देश भर में कानून की जो हालत है वह सुधर रही है । एक दफा फिर जनता ने, अवाम ने अपनी आस्था दिखायी है, लोकशाही की प्रक्रिया में और आतंकवादियों को बहुत बड़ा सबक सिखाया है, पंजाब में चुनाव के माध्यम से । मैं माननीय गृह मंत्री जी से पहले सवाल यह पूछना चाहूंगी कि क्या आप यह प्रक्रिया, जो पोलिटिकल प्रोसेस है, कश्मीर के बारे में अभी आपने बताया कि वहां असेंबली के चुनाव करवाने जा रहे हैं, पहले लोकल बाडीज के करवायेंगे-तो मैं जानना चाहती हूं कि कितनी जल्दी आप यह पोलिटिकल प्रोसेस कश्मीर में लागू कराना चाहेंगे, यह मेरा पहला प्रश्न है ? दूसरा मेरा,

श्री सभापति : एक ही प्रश्न आप कर सकती हैं ।

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : मेरे प्रश्न का बी पार्ट यह है...

श्री सभापति : जल्दी जल्दी कह दीजिये ।

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : आज तो मुझको आप मौका दीजिये ।

SHRI S. JAIPAL REDDY: She is raising her maiden question as a Congress(I) Member. So, you must give her preference.

MR. CHAIRMAN: Next time when you meet her, she will...(*Interruptions*).

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : यहां कश्मीर से आये लोग अलग-अलग टैंटों में बस रहे हैं । मैंने अपनी आंखों से देखा है । दिल्ली कैम्पों का मैंने मुआइना किया है । जम्मू में भी बहुत सारे परिवार बाहर बस रहे हैं । उनके लिये न खाने की सुविधा है, न रहने की

सुविधा है और न स्कूल है । यह मंत्री महोदय ने इसीलिये उनके रीहैबलीटेशन का कार्यक्रम बनाया है । लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि आप कश्मीर में ऐसे हालात कब पैदा करेंगे जब कि वे फिर से अपने मादरे-वतन में जाकर बस सकें ? दूसरी बात यह है कि जो आक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर कमांडो ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, आतंकवादियों को वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है, तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि उनको आप कब डिसमेंटल करेंगे ?

SHRI S. B. CHAVAN: Sir, there are three questions in one.

About the first part of the question, I would like to say that we are still to make an assessment. We have still not made it. So, I cannot give an exact date when the elections are going to be held.

Secondly, about the rehabilitation of those who have migrated from that area, gone over to Jammu or Delhi, in fact, we are interested in sending them back to Jammu and Kashmir so that they are able to participate in the elections as early as possible. But, in the meanwhile the rehabilitation measures are also seriously being undertaken.

About the third part of the question, the training which is being imparted to those who are almost forcibly taken to Pak-occupied Kashmir or even Pakistani areas, we have taken up these issues at different times with the Government of Pakistan.

MR. CHAIRMAN: Mr. Jagmohan.

SHRI VIREN J. SHAH: When we show that in our map and claim it to be a part of India, could we not take action there?

MR. CHAIRMAN: I think there is only one Jagmohan in this House.

SHRI V. NARAYANASAMY: What was the response of the Pakistan Government?

SHRI JAGMOHAN: My question is whether the hon. Minister is aware that there is a very serious problem of internal subversion in Kashmir; whether it is a fact that the DIG of Security whose job is to provide security to others, has himself been kidnapped and that there is no trace of him for the last two months; whether the Government is also aware that at the dictates of the terrorists a large number of subordinate officials are being recruited in the Kashmir valley and also contracts are being awarded to them, that actually no work is done, and only money is passed on to them.

SHRI S. B. CHAVAN: Sir, in fact, there might be a few cases. I would not be able to give the exact details. But I cannot rule out the possibility of some of the officers giving contracts to terrorists or to their agents also. That possibility is there because in the administration there are a few, who, in fact, are involved. But there are others, who are in large numbers, who, in fact, are not involved in this and because of the fear of guns they are almost forced to do certain things. We will have to make distinction beween those who are committed to terrorist ideology and all others who, because of the fear, have practically no alternative. So, that kind of a situation we have to handle. It is the responsibility of the State Government. In fact, I have given constant instructions to the administration there that the kind of alienation that I find in Jammu and Kashmir has to be removed and a sense of belonging has to be created. In fact, we are trying our level best to create that kind of an atmosphere of confidence.

कुमारी सईदा खातून: माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि कश्मीर घाटी में कट्टरवाद और हिंसा को कम करने के लिए आपने जो कदम उठाए हैं बेशक वह सराहनीय हैं लेकिन क्या आपने जनगणना की नीति अपनाने की कोशिश की है । बार बार जन-

गणना कर के यह देखा जाए कि किन किन घरों में टेररिस्ट लोगों को पनाह दी जाती रही है। इस जनगणना की नीति के मुताबिक आप एक साल के बाद जनगणना करते हैं। मेरा यह सुझाव है कि आप टेररिस्ट लोगों को पनाह देने वालों की क्वार्टरली जनगणना करें तो उचित रहेगा। इससे आपको पूरी सूचना मिल सकेगी। इसलिए आप इसको मेरा एक सुझाव ही समझ लीजिए, क्या आप इस नीति को अपनाने की कोशिश करेंगे ?

श्री एस० बी० चव्हाण : सभापति महोदय, पंजाब और जम्मू-कश्मीर दोनों स्टेट्स के अन्दर यह हालत है कि जिनके पास पनाह मांगी जाती है वह जबरदस्ती मांगी जाती है। अगर यह लोग पनाह न दें तो उनको गोली का निशाना बनाया जाता है। ऐसी हालत में मजबूरी में अगर कोई पनाह देने को मजबूर हो जाए, खाना खिलाने के लिए मजबूर हो जाए, अपने घर में ठहराने के लिए मजबूर हो जाए, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उनके साथ बदसलूकी होने के बावजूद भी वे कुछ कहने की हालत में नहीं रहते हैं। ऐसी हालत कुछ जगह पर जरूर थी। आहिस्ता आहिस्ता उसमें तबदीली आ रही है और एक सेंस आफ कानफिडेंस आ रहा है। अगर उन्होंने कोई चीज हमारे सामने बयान करने की कोशिश की तो उनको इस बात का इत्मीनान हो कि वहां की सिक्युरिटी फोर्सेज उनकी पूरी तरह से हिफाजत कर सकेंगी।

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Because of the unfortunate happenings in the Valley of Kashmir, its economy has really suffered a lot and because of that the people of the Valley have really suffered. The majority of them are not with the terrorists. We all know that. They are very much with India and they are patriotic as well. But, unfortunately, because of the setback the economy has suffered, has the Government made any kind of a 'master plan' to revive the economy of Kashmir? If so, what are the details. Of course, we know that Kashmir is going to come back to normalcy. I have no doubt about that.

SHRI S. B. CHAVAN: It is a fact that the economy of Jammu and Kashmir has really suffered very badly. Everything possible needs to be done for restoring normalcy in that area and bringing back the kind of a situation where they will feel that their economy has come on an even keel. The Government is trying its level best to find out how to do it. The main point is if such a measure has to be evolved, how we are to proceed. I don't find any person who has been going to that area who would come back and tell us that these are the grievances of the people and what measures the Government should take in the matter. That is why I propose to send some people. I will myself go to Jammu and Kashmir and discuss matters with some people and to the best of my ability, if possible, we will take some measures. I cannot possibly assure this House that this kind of measures can be announced before the Assembly elections. If it can be after the elections, then only the new Government will be able to talk to and finalise the issue.

श्री सभापति : श्री चतुरानन मिश्र। संक्षेप में सवाल कीजिये।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय म सरकार से जानना चाहता हूं कि भारत में जो हिन्दू फंडामेंटलिज्म है जिसके चलते पांच सौ साल पुराना बाबरी मस्जिद वगैरह का सवाल उठा है, क्या वह भी कश्मीर के फंडामेंटलिस्ट्स को प्रभावित करता है। अगर ऐसा होता है तो माननीय मूल प्रश्नकर्ता की अध्यक्षता में कोई गुडविल मिशन भारत में बनेगा जो हिन्दू फंडामेंटलिज्म की जांच करे ?

श्री एस० बी० चव्हाण : फंडामेंटलिस्ट्स चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों कोई खास फरक नहीं है। दोनों एक ही ढंग का काम करते हैं। इतना ही है कि जहां जहां कन्वीनियट होता है वह एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन इससे जो असल मामला है वह कभी तय नहीं हो सकता है। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म . . . **(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : हमने यह पूछा कि यहां का जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट है इसक वहां कश्मीर के फंडामेंटलिस्ट पर कोई रिएक्शन होता है असर होता है या नहीं। यह हमने पूछा है। अगर होता है तो ... **(व्यवधान)**

दूसरा पूछा था कि जो मूल प्रश्नकर्ता हैं उनकी अध्यक्षता में शेष भारत में कोई गुडविल मिशन बनाएंगे या नहीं जांच करने के लिए ?

श्री एस. बी. चव्हाण : : मैं समझता हूं कि इसी बात की कोशिश... **(व्यवधान)**

यह जो फंडामेंटालिज्म है इसको ही वहां पर कुछ इस किस्म की भावना पैदा करने के लिए एकता यात्रा वहां पर ले जाने की कोशिश हुई लेकिन उसका क्या असर हुआ है हम सब लोगों ने देखा है। इसलिए रिलीजियस फंडामेंटलिज्म चाहे वह हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, या किसी का क्यों नहीं हो, उससे कोई मसला... **(व्यवधान)**

श्री कृष्ण लाल शर्मा : आपने एलाउ क्यों किया। अगर इतना खतरनाक था तो एकता यात्रा को क्यों एलाउ किया।

श्री एस. बी. चव्हाण : आप अपने अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए कि हमने एलाउ किया या उन्होंने मांगा था।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : हमने मांगा। इसके बावजूद भी आपने एलाउ क्यों किया। अगर वह हानिकारक थी देश के लिए खतरनाक थी तो आपने एलाउ क्यों किया... **(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय सभापति जी मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि पाकिस्तान लोगों की धार्मिक भावनाओं का नाजायज फायदा उठा रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार को जानकारी है कि देश में कुछ संगठन और राजनैतिक दल भी जम्मू और काश्मीर में लोगों की धार्मिक भावनाओं को उभाड़कर नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। यदि यह सत्य है तो ऐसे कौन कौन से संगठन हैं और उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। मेरे प्रश्न का "ब" भाग है कि पाकिस्तान से सहायता प्राप्त तथा उसके द्वारा भड़काए गई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण जो स्थिति वहां पैदा हो रही है क्या उस संबंध में सरकार की ओर से कोई श्वेत पत्र जारी करने का इरादा है वैसे ही जैसे कि पंजाब के संबंध में किया गया है।

श्री एस. बी. चव्हाण : ये कौन कौन से आर्गेनाइजेशंस हैं मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी सारे लोगों को है। जितने टेरोरिस्ट आर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान की तरफ़ से उनको मदद मिलती है, वे सारे के सारे टेरोरिस्ट्स ही नहीं बल्कि फंडामेंटलिस्ट भी हैं। ... **(व्यवधान)** और वहां जो धार्मिक भावनाएं हैं लोगों की, उनका धर्म के ऊपर विश्वास है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन धार्मिक भावनाओं को उभाड़कर अगर वे उसका फायदा ले जा सकते हैं तो उस बात की कोशिश में वे हैं। दूसरा सवाल... **(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अभी तो मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मेरा प्रश्न था अभी जो राजनैतिक संगठन हैं उनके नाम क्या हैं और उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। "ब" भाग यह था कि वहां की गतिविधियों के संबंध में जो आतंकवाद का वहां बढ़ावा हुआ है हिंसा चल रहा है इसके संबंध में क्या सरकार की ओर से कोई श्वेत पत्र व्हाइट पेपर जारी करने का इरादा है ?

श्री एस. बी. चव्हाण : पहला सवाल जो है। उसके बारे में मैं अभी पूरे नाम नहीं ले सकूंगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : कुछ नाम ले लीजिए ।

श्री एस. बी. चव्हाण : लेकिन जो इम्पारटेंट किस्म के नाम हैं उनमें हिजबुल मुजाहिदीन है, अल उमर है, जे०के०एल०एफ० है । अभी 5–6 मोटे मोटे हमारे दिमाग में हैं वे मैं आपके सामने रख रहा हूं ।

श्वेत पत्र निकालने का सवाल अभी गवर्नमेंट के सामने नहीं है ।

Environmental problems posed by tanneries in Tamil Nadu

*302. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that tanneries in Tamil Nadu are causing environmental problems in that region;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what measures Government have taken to remedy the situation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) Yes, Sir. The major tannery centres in Tamil Nadu are Ranipet, Ambur, Vaniyambadi and Pernampet in North Arcot District, Pallavaram in Changalpet District, Erode in Periyar District, Dindigul in Anna District, Tiruchireppalli in Tiruchirpelli District and Madras. About 95 per cent of these are in the small scale sector. The structure of the industry, inadequate space to set up effluent treatment plants, lack of technical, managerial & financial capacities of the tanneries and also lack of access to sound technologies are among the factors that are responsible for environmental problems caused by these units;

(c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Regarding environmental problems posed by tanneries in Tamil Nadu.

The Government have already taken a number of steps for control of pollution from tanneries. The salient steps are as under:—

(i) Effluent standards for tanneries have been prescribed under the Environment (Protection) Act, 1986;

(ii) Environment guidelines have been evolved for sitting and operation of industries including tanneries;

(iii) Tanneries and clusters of tanneries have been asked to comply with consent requirements of the State Pollution Control Boards to limit the discharge of effluents within the stipulated standards;

(iv) The Central Government, in consultation with the State Governments, have issued a notification for industries, including tanneries to meet the effluent standards;

(v) Fiscal incentives are provided for installation of pollution control equipment in tanneries and also for the shifting of tanneries from congested areas;

(vi) Network of ambient air quality and ambient water qualty monitoring stations have been set up to measure pollution loads from industrial outfalls, including tanneries;

(vii) The State and the Central Government have provided subsidies to assist tanneries to set up common effluent treatment plants. So far the Central Government has given 4.94 crores to common effluent treatment plants at 8 locations in Tamil Nadu;

(viii) Under the World Bank aided project, initiated in November, 1991, the State and the Central Government would provide subsidies and loan to assist clusters